

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:- मेघना चौधरी, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:-64/2019/223 (2019/00064)

1. पोलू दत्तक पुत्र स्व० रामनाथ, जाति खारोल, निवासी सूरजपुरा, तह० सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांत

बनाम

1. भैरू पुत्र घीसा,
2. जगदीश पुत्र मोती,
3. महावीर पुत्र मोती,
4. गोपाल पुत्र मोती,
5. सांवरा दत्तक पुत्र मेघा,
6. रतनी पुत्री नंदा,
7. हगामी पुत्री नंदा,
8. समस्त जाति खारोल, निवासी सूरजपुरा, तह० सरवाड़, जिला अजमेर ।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोंडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध विरुद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 24.11.2017 अंतर्गत वाद संख्या 65/2015 .

उपस्थित:-

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांत ।
2. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील रेस्पोंड संख्या 1 लगायत 7.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंड संख्या 8.

निर्णय

दिनांक:- 5.10.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.11.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपीलांत/वादी ने अधी०न्याया० के समक्ष प्रतिवादीगण/रेस्पोंड संख्या 1 लगायत 7 के विरुद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188, 92- एवं 53 राज०काश्त०अधि० 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात गत खसरा नंबर 88 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 103 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा कुल कित्ता 2 कुल रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम सूरजपुरा, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर में अवस्थित है । राजस्व अभिलेख अनुसार विवादित आराजियात अपीलांत व रेस्पोंड संख्या 1 लगायत 7 की सहखातेदारी की आराजियात है । उपरोक्त आराजियात सांवरा पुत्र मेघा, भैरू पुत्र घीसा, मोती पुत्र रूघा, रोड़ी बेवा घीसा, भैरू, सांवरा पि० घीसा 2/3 हिस्सा, नंदा पुत्र गिरधारी 1/9 हिस्सा, हगामी पुत्री नंदा 2/9 हिस्सा दर्ज है जिसमें मोती के स्थान पर वारिसान पोलू तथा रेस्पोंड संख्या 1 लगायत 3 का नाम दर्ज है । इसी प्रकार खसरा

DR
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर



संख्या 27 रकबा 23 बीघा 1 बिस्वा, 28 रकबा 3 बिस्वा, 41 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 48 रकबा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 107 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा जमाबंदी अनुसार सावरा पुत्र मेघा, भैरू पुत्र घीसा, पोलू, जगदीश, महावीर, गोपाल पि० मोती, भैरू व सावरा पि० घीसा व नंदा पुत्र गिस्थारी के खाते में दर्ज है। नंदा फौत हो जाने से हमाम व रतनी पुत्रियां नंदा का नाम दर्ज किया गया है। जबकि अपीलांट/वादी जाति रिवाज व धर्म अनुसार रामनाथ के गोद आ गया था एवं रामनाथ की सम्पत्ति पर ही बतौर काबिज चला आ रहा है। उक्त अनुसार वादी खातेदार घोषित किया जाकर वादी के हिस्से में आई भूमि का विभाजन करवाकर हिस्सा अलग करवाना चाहता है। अतः विभाजन की आज्ञापति प्रदान की जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी को पाबंद किया जावे। उक्त वाद प्रस्तुत होने के उपरांत एक अन्य वाद रेस्प० संख्या 1 लगायत 7/प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु उपरोक्त आराजियात व खसरा संख्या 80 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम प्रतापपुरा को सम्मिलित करते हुए पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात अविभाजित है जिसका विधिवत् बंटवारा किया जाना आवश्यक है। इसलिये वादवर्णित आराजियात का विभाजन किया जाकर जमाबंदी जारी किए जाने की आज्ञापति पारित करे एवं स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञापति प्रदान की जावे। अधी० न्याया० ने उपरोक्त वादों को समेकित करते हुए रेस्प०/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में जवाबदावा निहित होना वर्णित करते हुए चार तनकियात कायम की तथा प्रकरण को वास्ते साक्ष्य हेतु नियत किया गया। पत्रावली में पक्षकारान की साक्ष्य लिए बिना लोक अदालत शिविर रामपाली में प्रकरण को नियत कर वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर रेस्प०/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाकर विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का निर्णय व डिक्री दिनांक 4.6.2016 को पारित की। तत्पश्चात् अधी० न्याया० ने कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 24.11.2017 को वाद में अंतिम डिक्री पारित की। अधी० न्याया० द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.11.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट/वादी ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी० न्याया० का निर्णय व अंतिम डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी० न्याया० के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद के पश्चात् रेस्प०/प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। उक्त वादपत्र को अपीलांट के वादपत्र के साथ समेकित किया जाकर अधी० न्याया० द्वारा उपरोक्त पश्चात्वर्ती वाद में दावे का जवाब निहित होना वर्णित करते हुए तनकियात कायम की एवं इसके पश्चात् पत्रावली वास्ते शहादत हेतु नियत की गई है जिसमें बिना पक्षकारान कही शहादत लिये पत्रावली को राजस्व कैम्प लोक अदालत में रखकर प्रकरण में निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 4.6.2016 से अपीलांट के वाद को निरस्त करते हुए रेस्प० द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किये जाने के आदेश पारित किये हैं इसके पश्चात् एकपक्षीय रूप से कार्यवाही की जाकर प्रकरण में बिना पक्षकारान की सुनवाई के उक्त प्राथमिक डिक्री के आधार पर पटवारी हल्का अजगरा द्वारा प्रेषित नक्शा कुरेजात व बंटवारा प्रस्ताव को आधार मानकर अंतिम डिक्री पारित की है जो प्रथम दृष्टया न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी० न्याया० द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को एकपक्षीय डिक्री किया जाकर अंतिम डिक्री बाबत तहसीलदार



DR
राजस्थान न्यायालय राजस्थान अपील प्राधिकरण

सरवाड को स्वयं मौके पर जाकर आवश्यक कुरेजात मंगाये जाने के आदेश दिए गए हैं इसके विपरीत दिनांक 3.7.2017 को पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक अजगरा द्वारा बनाए गए कुरेजात को दिनांक 2.8.2017 को प्रेषित किया गया है एवं उक्त कुरेजात के आधार पर आज्ञात्मक प्रावधानों के विपरीत अंतिम डिक्री पारित की है। नियम 18 से 21 राजस्व मेन्यूअल के प्रावधानों के विपरीत पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक ने कुरेजात रिपोर्ट में सड़क से लगती हुई भूमि रेस्पों की खातेदारी में रखकर अपीलान्ट को पीछे के हिस्से में भूमि दी है। ऐसी रिपोर्ट के आधार पर अधीन्याया ने वाद में अंतिम डिक्री पारित करने में त्रुटि कारित की है। पटवारी हल्का ने उक्त कुरेजात रिपोर्ट एकपक्षीय तैयार की है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। पटवारी हल्का द्वारा तैयार कुरेजात रिपोर्ट विधिअनुसार मान्य नहीं है। अधीन्याया के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण प्राथमिक डिक्री के उपरांत वास्ते अंतिम डिक्री हेतु तहसीलदार को मौके पर जाकर नक्शे कुरेजात आदेश पारित किया जाकर लंबित रखी गई है उक्त अनुपालना में बिना पक्षकारान को नोटिस जारी किए बिना तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित नक्शा कुरेजात को विचारण न्यायालय को प्रेषित किया गया है जिसके आधार पर अधीन्याया ने अंतिम डिक्री पारित की है जो विधिविरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीन्याया द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.11.2017 निरस्त की जावे तथा पत्रावली में पक्षकारान की शहादत ली जाकर विधिवत् रूप से सुनवाई कर निर्णय पारित किए जाने हेतु अधीन्याया को प्रतिप्रेषित किया जावे।

5. विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधीन पेश कर कथन किया कि अधीन्याया ने आक्षेपित निर्णय पारित करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया तथा प्रकरण को राजस्व अभियान के दौरान लोक अदालत में रखकर निर्णय पारित किया है। निर्णय की जानकारी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को नहीं दी गई। तत्पश्चात् अधीन्याया द्वारा कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 24.11.2017 को वाद में अंतिम डिक्री पारित कर दी गई। हाल ही में दिनांक 18.2.2019 को प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजियात जो कि रामनाथ के हिस्से की आराजियात रही है पर जबरन दखलदांजी करने पर प्रार्थी ने पटवारी हल्का से संपर्क किया तो पटवारी हल्का ने अधीन्याया द्वारा पारित निर्णय के संबंध में अवगत कराया जिस पर प्रार्थी ने अधीन्याया के निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब उचित है। अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2018-19 सप्लीमेंट्री पेज 394 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया।
6. विद्वान वकील रेस्पों संख्या 1 से 7 ने बहस में कथन किया कि अधीन्याया का निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत है। अधीन्याया के समक्ष अपीलान्ट द्वारा भी वाद पेश किया गया था जिसमें वे एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित रहे हैं। अधीन्याया ने दिनांक 4.6.2016 को वाद प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार को कुरेजात रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिये थे जिसकी जानकारी अपीलान्ट को प्रारंभ से थी। तहसीलदार ने 18 से 21 की पालना कर बंटवारा के प्रस्ताव अधीन्याया को भिजवाये हैं जिसके आधार पर अधीन्याया ने अंतिम डिक्री पारित की है। यदि अपीलान्ट को अंतिम डिक्री से कोई आपत्ति थी तो इन्हें अधीन्याया के समक्ष ऐतराज पेश करना चाहिये था किन्तु अधीन्याया के समक्ष ऐतराज पेश नहीं कर अपील न्यायालय में ऐतराज पेश किये हैं जो उचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। विद्वान वकील रेस्पों



AS-
राजस्व अपील प्रमाणिक
अजगरा


ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2010 पेज 289, आर0आर0डी0 2002 पेज 26 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

7. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते हैं । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये हैं वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते हैं । हम न्यायहित में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते हैं । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।
8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/रेस्पों द्वारा बंटवारे का वाद पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 4.6.2016 को बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार, सरवाड़ को कमिश्नर नियुक्त कर राजस्व मेन्युअल नियम 18 से 21 के अनुसरण में मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का बंटवार प्रस्ताव तैयार करवाने के निर्देश दिये । अधी0न्याया0 के निर्णय की पालना में तहसीलदार, सरवाड़ ने दिनांक 2.8.2017 को बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अधी0न्याया0 को प्रेषित किये हैं । उक्त बंटवारा प्रस्ताव पर तहसीलदार सरवाड़ के हस्ताक्षर हैं जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार सरवाड़ द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं किये गये हों । तहसीलदार ने बंटवारा प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार राजस्व मेन्युअल के नियम 18 से 21 के अनुसरण में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तैयार कराकर अधी0न्याया0 को भिजवाये हैं । अधी0न्याया0 ने उक्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर वाद में अंतिम डिक्री पारित की है । यदि अपीलांट को बंटवारा प्रस्ताव से कोई आपत्ति थी तो उन्हें अधी0न्याया0 के समक्ष ऐतराज पेश करने चाहिये थे किन्तु अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष कोई ऐतराज पेश नहीं किये गये हैं । अधी0न्याया0 ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।
9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा वाद संख्या 65/2015 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.11.2017 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हों ।


(मेघना चौधरी)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 5.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।


(मेघना चौधरी)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

